साप्ताहिक

RNI No.- CHHHIN17077

प्रथम आवाज़

वर्ष- 04, अंक- 06, कीमत- 3.00 रुपए, कुल पृष्ठ- 04 | सारंगढ़, गुरुवार, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 | Email- Pratham.awaaz@gmail.com

सरसींवा बनेगा तहसील, सरसींवा और पवनी बनेंगे नगर पंचायत : मुख्यमंत्री ने की घोषणा

बिलाईगढ़ में खुलेगी नवीन जिला सहकारी बैंक की शाखा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में होगा उन्नयन

❑ भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से हुए रुबरु

प्रथम आवाज | सारंगढ़-बिलाईगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरसींवा पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने ग्रामीणों से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत की जानकारी भी ली एवं अधिकारियों को इसके निराकरण के लिए निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां पर आम जनता की सुविधा के लिए सरसींवा को नवीन तहसील बनाए जाने एवं सरसींवा और पवनी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने सरसींवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन, बिलाईगढ़ में नवीन जिला सहकारी बैंक की शाखा, बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिस्तर क्षमता 30 बिस्तर से बढ़ा कर 50 बिस्तर किए जाने सहित बिलाईगढ़ नगर पंचायत में बस्ती पहुंचने एवं बस्ती से बाजार पहुंचने हेतु पुलिया का निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति किए जाने की घोषणा की। इस मौके पर स्कूली शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव चन्द्रदेव प्रसाद राय, अ.जा. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

ग्रामीणों से लिया फीडबैक- भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्राम धोबनी के किसान कोमल प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका एक लाख 10 हजार का ऋण माफ हो गया है। उन्हें अब तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीन किस्त मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि वे जैविक पद्धति से बैगन की खेती करते हैं। पांच साल धान की खेती के बराबर लाभ एक साल के बैगन की खेती से होता है। पिछले साल बैगन की खेती से 5 लाख रुपए का फायदा हुआ है। जैविक खेती से जमीन की उर्वरता बढ़ी है। प्रमिला यादव ने बताया कि स्व-सहायता समूह से जुड़कर उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। वह वर्मी कंपोस्ट, मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, कड़कनाथ पालन जैसी आयमूलक गतिविधियां कर रही हैं। इससे अब तक उसे 45 हजार रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। कैथा निवासी सुदर्शन दास की मांग पर कलेक्टर को मनरेगा और गौठान में काम दिलाने तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राशि देने एवं उनकी बीमारी का इलाज कराने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में चेतन बाई महिलांग ने कहा कि उनका एक लाख 56 हजार की ऋण की माफी हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नरेश कुमार को सेलून खोलने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री ने सुनाया अनुभव- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की शुरूआत में भेंट मुलाकात का अनुभव बांटते हुए कहा कि भेंट मुलाकात के दौरान एक 40 वर्षीय महिला गेड़ी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की गेड़ी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से अब महिलाएं भी अपने बचपन में खेले जाने वाले खेल फिर से खेल पा रही हैं। उन्होंने कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया। इनमें बिलाईगढ़ और भटगांव के 8 दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल और दो दिव्यांगजनों को वैशाखी के साथ ही स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने रामनामी परिवार के यहां किया भोजन- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम सरसीवां में नेतराज कुर्रे के घर रामनामी समुदाय के लोगों के साथ छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का स्वाद लिया। उन्हें भोजन में चावल, खीर, रोटी, लाल भाजी, तिवरा भाजी, करेला भाजी, बैंगन, मटर, आलू, सेमी, फूलगोभी मिक्स, पालक, आलू की सब्जी दाल, सहित सील से पीसे टमाटर चटनी परोसा गया। मुख्यमंत्री ने कुर्रे के परिवारवालों को स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद दिया।

भटगांव में उप पंजीयक कार्यालय खोलने की घोषणा

❑ बिलाईगढ़ में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की भेंट-मुलाकात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम बिलाईगढ़ में विभिन्न समाज एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल से भेंट-मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान भटगांव में उपपंजीयक कार्यालय खोलने की घोषणा की।

बिलाईगढ़ में बस सुविधा दुरूस्त करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। उन्होंने इस मौके पर एक-एक कर सभी समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही उनसे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से भेंट-मुलाकात के दौरान टुण्डाऊ रोड की मरम्मत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। खैरवार समाज की मांग पर रंगमंच निर्माण के लिए 5 लाख रूपए स्वीकृत करने के निर्देश दिए। खैरावार समाज प्रमुखों ने समाज के लोगों को पूर्व में दिए गए वन भूमि पट्टा को दुरूस्त किए जाने की बात कही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर शासन को प्रस्तुत करने की समझाइस दी। वैष्णव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को सारंगढ़ में आगामी 11 एवं 12 फरवरी को आयोजित होने वाले महाअधिवेशन में आने का निमंत्रण दिया। मुस्लिम समाज द्वारा कब्रिस्तान के बाउंड्रीवाल निर्माण की मांग पर मुख्यमंत्री ने बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए स्टीमेट के अनुरूप राशि देने की बात कही। केंवट समाज द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखने का आवश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री को जायसवाल कलार समाज प्रमुख ने सामाजिक बोर्ड की गठन की मांग की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक भवन के लिए जमीन की रजिस्ट्री समाज के नाम पर कराने की समझाईश दी। उन्होंने कहा कि जमीन रजिस्ट्री के बाद ही प्रक्रिया के तहत राशि आबंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहार समाज द्वारा बिलाईगढ़ में मुक्तिधाम की मांग पर सहमति व्यक्त करते हुए कलेक्टर को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न समाजों की मांग पर सामाजिक भवन और अन्य कार्यों के लिए करोड़ों रूपए की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अघरिया समाज को बिलाईगढ़ में सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रूपए, ग्राम चांदन, देवरी सोनाखान क्षेत्र में अघरिया समाज के सामुदायिक के लिए 20 लाख रूपए, गिरौदपुरी में पटेल मरार समाज के सामाजिक भवन के लिए 15 लाख रूपए, साहू समाज के लिए पुरगांव, धनसिर में कंवर समाज, चौहान समाज, गोंड समाज और संवरा समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 10-10 लाख रूपए, वैष्णव समाज को भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए स्वीकृत किए।

जिला बनने के बाद भी नही सुधर रहे पटवारी, हल्का में रहने के निर्देश का हो रहा उल्लंघन

सारंगढ़ में दफ़्तर खोल असिस्टेंट के माध्यम से वसूली का खेल चालु

प्रथम आवाज | सारंगढ़

सारंगढ़ राजस्व अंतर्गत आने वाले सभी किसान पटवारियों से परेशान है। आपको बता दें,सभी पटवारी अपने हल्का को छोड़कर खुद का निजी कार्यालय खोल कर बैठे हैं,जैसे डॉ निजी क्लीनिक खोल कर बैठे है ठीक उसी तरह सारंगढ़ स्थित सभी पटवारी अपने निजी कार्यालय खोल रखें है। जिससे किसानों को सारंगढ़ पटवारी के निजी कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है, कई किसान बुजुर्ग ऐसे भी है। जिनको सारंगढ आने-जाने में दूसरे लोगों की मदद की जरूरत होता है और जो किसान साराँगढ़ पटवारी के निजी कार्यालय नही पहुँच पाते उनका पंजीयन ही नही हो पाता है! क्योंकि किसान पटवारी के निजी दफ्तर का चक्कर काटते रह जाते है। वही सभी हल्का नंबर में सरकार पटवारी भवन बना रखा है जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना न पड़े। लेकिन पटवारियों के करतूत यह है कि निजी दफ्तर में किसानों को बुला कर पंजीयन,खाता दुरुस्ती या अन्य कामों के पैसा वसूल सके! सरकार ने अन्य दफ्तरों की तरह पटवारीयों के लिए भी पटवारी भवन बना रखे है बावजूद पटवारी अपने हल्का से नदारत रहतें है!

यही नही कई पटवारी ऐसे भी है जो काम करने के लिए मंथली वेतन पर असिस्टेंट रखें हुए है, अब सोचने वाली बात यह है कि असिस्टेंट को मंथली वेतन देने के लिए पैसा कहां से आता है! क्या पटवारी अपने वेतन से भुगतान करता है या फिर किसानों से पैसा लेकर?

पटवारी के असिस्टेंट से किसानों को भुगतना पड़ सकता है बड़ा खामियाजा- आपको बता दें जमीन बटवारा में भाई-भाईका नहीं होता न ही बाप बेटे का ऐसे में अगर पटवारी का असिस्टेंट से गलती से किसी किसान का रखबा कट जाए उस स्थिति में क्या होगा? पटवारी एक किराए के व्यक्ति को सरकारी काम काज व राजस्व में दखल देने में कोई कसर नही छोड़ रहे!

स्थानीय विधायक व सरकार को छति पहुँचा सकता है पटवारीयों की लापरवाही- आपको बता दें गाँव मे बड़े बुजुर्ग किसानों को उनके कोई भी काम नही होने या काम संबंधित तखलीफ़ परेशानी होता है तो सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगाते है या स्थानीय विधायक,नेताओं के ऊपर आरोप लगाते है कि ये सरकार या इनके सरकार में कोई काम नही हो पा रहा है! यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है पटवारीयों की लापरवाही से किसानों को मिलों दूर चल कर जाना पड़ रहा है जहाँ पर सारंगढ पटवारी अपने हल्का क्षेत्र को छोड़कर निजी दफ्तर खोल रखें है जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शराब के नशे में धूत दोस्तों ने की अजय कुर्रे की हत्या, सारंगढ़ पुलिस ने चंद घंटो में सुलझाया हत्या का मामला

सारंगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कटेकोनी का मामला, तीनो आरोपी को भेजा जेल

❑ अवैध शराब पर सारंगढ़ पुलिस का नियंत्रण नही, नशा के कारण क्षेत्र में बढ़ रहा अपराध

प्रथम आवाज | सारंगढ़

घटना का इस प्रकार है कि दिनांक 19/12/2022 को थाना कोतवाली सारंगढ़ को सूचना मिली की ग्राम कटेकोनी मुख्य मार्ग पर एक युवक की लाश पड़ी हुई है। मामला प्रथम दृष्टया हत्या का लग रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय चौधरी मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देकर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जहां सूचक घनश्याम कुर्रे ने बताया कि इसका पुत्र अजय कुर्रे 18 मार्च 2022 की रात को लगभग 8:00 बजे मेला देखने जा रहा हूं कहकर निकला था जो रात भर से घर नहीं आया।

सुबह गांव में हल्ला हुआ कि गांव के बाहर होरी डोली के पास इसके लड़के अजय का शव पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही प्रार्थी मौके पर जाकर देखा तो इसके लड़के अजय कुर्रे के सर व चेहरे के बाई भाग पर गंभीर चोट के निशान थे। घनश्याम कुर्रे ने बताया कि रात्रि में गांव के हंसराज निराला और जसवंत निराला के साथ उसके पुत्र को घूमते हुए देखा गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मौके पर ही मर्ग कायम करते हुए धारा 302 का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, उप पुलिस अधीक्षक स्नेहिल साहू स्वयं मौके पर उपस्थित हुए और घटनास्थल का बारीकी से अवलोकन कर थाना प्रभारी विजय चौधरी को इन्वेस्टिगेशन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जिसका पालन करते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए संदिग्धों को उनके घर से धर दबोचा साथ ही अपने लोकल सूचना तंत्र के माध्यम से घटना के संबंध में प्रारंभिक जानकारी निकाल ली। मुखबिरो से मिली जानकारी और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर सारंगढ़ पुलिस ने कुछ घंटों में ही अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। पूछताछ पर संदेहियों ने बताया कि कल रात 8:00 मृतक अजय कुर्रे और आरोपी हंसराज निराला एवं जसवंत निराला ने पहले एक साथ शराब पी उसके बाद यह लोग और शराब पीने की इच्छा से गांव से बाहर की ओर आ गए तभी गांव के ही अमित कोसले और संतोष कुर्रे सारंगढ़ से ड्यूटी के बाद अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में इन तीनों ने अमित को रोक लिया और उसे शराब ढूंढने चलने को कहने लगे तब अमित संतोष कुर्रे को उसके घर छोड़कर उन तीनों को लेकर फिर शराब सेवन के लिए निकल पड़े। रात्रि लगभग 12:00 बजे चारों अत्यधिक शराब के नशे में आ गए। अजय कुर्रे शराब के नशे में तीनों से विवाद कर उन्हें गाली गलौज कर रहा था तब गुस्से में आकर पहले तो तीनों ने मिलकर उसे हाथ मुक्के लात से मारा जब वह जमीन पर गिर पड़ा तो हंसराज निराला में पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर पटक दिया जिससे मृतक के सिर और चेहरे के बाएं भाग पर गंभीर चोट आ गई और मौके पर ही अजय की मृत्यु हो गई। घटना के बाद अमित कोसले ने हंसराज और जसवंत को उनके घर छोड़ दिया और खुद भी घर जाकर सो गया। घटना में प्रयुक्त पत्थर को पुलिस ने सामने के खेत से बरामद कर लिया है और आरोपी हंसराज निराला, जसवंत निराला और अमित कोसले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

आरोपीगण– **1.** हंसराज निराला पिता वीर सिंह उम्र 19 वर्ष। **2.** जशवंत निराला पिता रूपेंद्र उम्र 19 वर्ष। **3.** अमित कोसले पिता साथी राम उम्र 23 वर्ष। **4.** सभी निवासी ग्राम कटे कोनी थाना कोतवाली सारंगढ़।

उक्त सक्रिय कार्यवाही में थाना प्रभारी विजय चौधरी एवं समस्त कोतवाली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सारंगढ़ रेल लाइन की स्वीकृति को लेकर केंद्रीय रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव से मिली सांसद गोमती साय, बहुत जल्द शुरू होगा काम

प्रथम आवाज | फरसाबहार

जशपुर एवं सारंगढ़ जिले में रेलवे लाईन बिछने का सपना सच करने का उद्देश्य लेकर क्षेत्र की सांसद गोमती साय ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की ओर उनके सामने जशपुर एवं सारंगढ़ जिले में रेलवे के जरूरी मांगो को दोहराते हुए बताया कि मेरे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जशपुर एवं सारंगढ़ जिले रेल लाइन से अछूते है। साय ने सारंगढ़ को जोड़ने के लिए बलौदाबाजार - सारंगढ़ - झारसुगुड़ा रेल लाइन एवं जशपुर जिले को जोड़ने के लिए कोरबा - पत्थलगांव - लोहरदगा, धर्मजयगढ़ - लैलूंगा - लोहरदगा, एवं अंबिकापुर - बगीचा - झारसुगुड़ा रेल लाईन को स्वीकृति देने के लिए रेल मंत्री के हाथ सभी रेल लाइन की मांग का अलग - अलग पत्र भी सौंपा।

केंद्रीय रेलमंत्री वैष्णव ने साय के मांग पत्र पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि ये सभी आवश्यक रेल लाइन है। मैं इन पर अवश्य ही कार्य करूंगा। साथ ही रेलवे के अधिकारियों को जानकारी के लिए निर्देशित भी किया।

गोमती साय लगातार जशपुर एवं सारंगढ़ में रेल लाईन को लेकर देश के सबसे बड़े सदन संसद में कई बार आवाज उठाई और देश के केंद्रीय रेलमंत्री के सामने भी इस मांग को उठाया। इनके कई बार के प्रयासों के बाद कोरबा से लोहरदगा रेल लाईन का सर्वे भी शुरू हो गया लेकिन इस प्रोसेस को गति देने के लिए इस बार वह रेल मंत्री से दुबारा मिली और फिर से रेल मंत्री को एक पत्र देकर जिले में रेल की जरूरतों से अवगत कराया।

विदित हो कि कुछ माह पहले लोहरदगा से कोरबा तक रेल लाईन के सर्वे की स्वीकृति मिल चुकी है इस तरह इस लाईन का 2 बार सर्वे भी हो चुका है।माना जा रहा है कि एक और सर्वे के बाद ग्रास रूट पर काम भी शुरू हो जाएगा।

कोटपा एक्ट के तहत हुई 14 चलानी कार्यवाही

प्रथम आवाज | सारंगढ़-बिलाईगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एफ.आर.निराला के मार्गदर्शन पर जिले भर के विभिन्न स्थानों पर छापा मार कार्यवाही की गई। जिसमें विकासखंड बरमकेला में 7, बिलाईगढ़ में 5 एवं सारंगढ़ में 2, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के क्रय-विक्रय कर्ता एवं सार्वजनिक स्थल पर उपयोगकर्ता के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई एवं इस मौके पर तंबाकू उत्पाद के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। ज्ञातव्य हो कि तंबाकू निषेध दिवस के दिन बड़ी संख्या में सार्वजनिक मंचों पर लोगों के द्वारा तंबाकू के सेवन नहीं करने एवं रोकथाम में अपनी योगदान देने की शपथ ली जाती है, परंतु अगले ही दिन से लोगों के द्वारा निष्क्रिय होकर स्वयं के द्वारा तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद के सेवन करते हुए देखा जाता है। ऐसे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.निराला ने समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिमाह कोटपा एक्ट के तहत चलानी कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिए हैं।

साप्ताहिक
प्रथम आवाज़
एक जन आंदोलन का आगाज
सारंगढ़, गुरुवार, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022

संपादकीय

पुरानी पेंशन योजना : समस्या नई नहीं विवाद है पुराना

वर्षों से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना, जो 2004 में अटल बिहारी बाजपेई की सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी और उसकी जगह नई पेंशन योजना शुरू की गई थी, सुर्खियों में है।

विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बना रही हैं। पुरानी योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देने की व्यवस्था थी जो उनके वेतन पर आधारित है। कर्मचारी आखिरी वेतन का आधा पेंशन के रूप में लेने के हकदार होते हैं। महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि का लाभ भी पेंशनधारियों को मिलता है। पेंशनधारी की मृत्यु पर उसके परिजन को भी पेंशन मिलती है। कर्मचारी को पेंशन के लिए सेवा की अवधि में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता। पेंशन का सारा खर्च सरकार उठाती है। पेंशन के अतिरिक्त मेडिकल भत्ता और बिलों की रिइंबर्समेंट के प्रावधान भी हैं। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी को 20 लाख तक की ग्रेच्युटी भी मिलती है। कर्मचारियों के लिए यह सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित योजना रही है। योजना को बंद करने के निर्णय के पीछे सरकार के राजस्व पर बढ़ता बोझ है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) जनवरी, 2004 से शुरू की गई। इसका संचालन पेंशन निधि विनायक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। कर्मचारी की आयु 60 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात उसे पेंशन दी जाती है। 18 से 70 वर्ष के आयु के नागरिकों के लिए यह उपलब्ध है। योजना बाजार संचालित रिटर्न पर आधारित है। पेंशन ग्राहक अपनी बचत को गैर-निकासी योग्य खाते में जमा करता है। कम से कम रुपये 500 से यह खाता खोला जा सकता है। खाते में जमा राशि निवेश की जाती है। सब्सक्राइबर के लिए तीन विकल्प होते हैं। उच्च जोखिम उच्च रिटर्न मुख्य रूप से इक्विटी मार्केट में निवेश, मध्यम जोखिम मध्यम रिटर्न, सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, एवं कम जोखिम कम रिटर्न सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। सभी चयनित परिसंपत्ति में खाताधारक का योगदान हंड्रेड परसेंट होता है। जितना योगदान कर्मचारी करेगा उतना ही उसे लाभ मिलेगा। खाते से संचित राशि निकालने की कोई सीमा नहीं होती, नामांकन की सुविधा भी होती है। निश्चित पेंशन की गारंटी इस योजना में नहीं होती। निवेश पर आयकर की धारा 80 सीसीडी के अंतर्गत डेढ़ लाख रु पये तक का टैक्स रिबेट मिलता है।

इस योजना के अलावा अटल पेंशन योजना भी है जो मई, 2015 में शुरू की गई थी, इसमें है 1000 से लेकर 5000 रुपये महीने की गारंटीड पेंशन जो 60 साल के बाद पेंशनधारक द्वारा जमा की हुई रकम के आधार पर मिलती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इनकम टैक्स में निवेश पर छूट भी ऊपर की योजना जैसी मिलती है। इन दोनों योजनाओं में सरकार की ओर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मार्च, 2022 में नई पेंशन योजना में 22 .48 लाख एवं राज्यों में 55.77 लाख सब्सक्राइबर थे।

सरकारी पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त बीमा कंपनियों द्वारा भी पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी एक वरिष्ठ बीमा योजना एलआईसी के माध्यम से प्रशासित है, जो एकमुश्त राशि के भुगतान पर पॉलिसी होल्डर को प्रति वर्ष 9त्न (मासिक आधार पर देय) की गारंटीकृत दर पर पेंशन देती है। योजना का आरंभ 14 अगस्त, 2014 को हुआ था। एलआईसी द्वारा सृजित रिटर्न के बीच अगर कोई अंतर होता है, तो भारत सरकार द्वारा योजना में सब्सिडी से इसकी भरपाई की जाती है। एलआईसी की एक योजना जीवन अक्षय भी है, जिसमें एकमुश्त रकम जमा करके पेंशन प्राप्त की जा सकती है। एसबीआई द्वारा सरल रिटायरमेंट सेवर योजना चलाई जाती है। निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां: आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मैक्स, बजाज अलायंस, एबीएसएलआई, कोटक आदि भी पेंशन योजनाएं चलाती हैं।

देश की आबादी 140 करोड़ है, सरकारी पेंशन पाने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है: डेढ़ करोड़ राज्यों में और 48 लाख केंद्र सरकार के अंतर्गत। अप्रैल, 2004 के पहले के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में हैं। उसके बाद जिन्होंने सरकारी सेवाएं ज्वाइन की हैं, वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत हैं। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी गई है, पंजाब और दिल्ली में भी योजना लागू होने जा रही है। पेंशन भुगतान पर पिछले 5 वर्षों में राज्यों के बजट में 48त्न की वृद्धि हुई, 2021-22 में सभी राज्यों का पेंशन पर खर्च 406867 करोड़ रु पये था जबकि राजस्व 1594665 करोड़ रुपये। कर्ज में डूबे 10 बड़े राज्यों : बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में राजस्व का 12.5त्न पेंशन पर खर्च हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल और मोंटेक सिंह अहलूवालिया सहित अनेक अर्थशास्त्रियों ने पेंशन पर बढ़ते खर्च पर चिंता व्यक्त की है। पुरानी पेंशन योजना यदि फिर से लागू कर दी जाए तो आने वाली पीढ़ी के ऊपर इसका बोझ तेजी से बढ़ेगा। इसे चुनाव जीतने के लालच में रेवड़ी बांटने की संज्ञा दी जा रही है, जो राज्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नकारा नहीं जा सकता।

हिमाचल प्रदेश में हाल के चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा था। 2021-22 में हिमाचल प्रदेश का कुल राजस्व 9282 करोड़ रु पये था और पेंशन पर होने वाला खर्च 7082 करोड़ रु पये। ऐसी स्थिति में विकास के कार्यों के लिए पैसा कहां बचेगा, रोजगार के नये अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे? वर्ष 2023 में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन योजना को बहाल के वादे कर सकती हैं, जिससे राज्यों की वित्तीय व्यवस्था और कमजोर हो सकती है। किंतु पेंशन सामाजिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, सरकार की जिम्मेदारी है, कर्मचारियों और आम जनता के हित में ऐसी पेंशन योजना आनी चाहिए जिसमें पेंशनधारी और सरकार, दोनों मिलकर खर्च वहन करें, सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आम वृद्ध नागरिक भी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा सकें। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकसित देशों की तरह भारत में भी सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यापक कानून की जरूरत है।

- प्रो. लल्लन प्रसाद

फिर बढ़ा कोरोना का खतरा : बीमारी से निपटने के लिए सरकार की रणनीति, एम्स में बुलाई बड़ी बैठक

नई दिल्ली

कोरोना ने दुनिया भर में एक बार फिर अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर चीन में यह अपना रौद्र रूप धारण कर चुका है। कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। ऐसे में अब भारत ने इससे निपटने के लिए अभी से पूरी सख्ती बरतने और सभी कोविड नियमों का पालन कराने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।

भारत सरकार सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि आज बुधवार दोपहर दो बजे देशभर में कोरोना टीकाकरण के अभियान को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बड़ी बैठक होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार एक बार फिर देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को और तेजी के साथ शुरू करने की रणनीति तैयार कर रही है। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और तीसरी यानी बूस्टर डोज लगाने का काम किया जा रहा है। 15 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। इससे जुड़े अभियान को लेकर खास चर्चा की जा सकती है।

बताते चलें कि चीन में जहां कोरोना हाहाकार मचाए हुए है। वहीं दुनिया के खासकर एशिया, यूरोप समेत कई देशों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना के वैश्विक मामलों में बड़ा उछाल रिकॉर्ड किया जा रहा है। गत 18 दिसंबर को कोरोना के आंकड़े यानी डेढ़ माह के भीतर 55 फीसदी उछाल मारे हैं। यह आंकड़ा अब 3.3 लाख से बढक़र 5.1 लाख पहुंच गया है जोकि आने वाले समय में दुनिया के लिए बेहद ही चिंताजनक बन सकता है।

एम्स में टीकाकरण को लेकर बुलाई गई बड़ी बैठक भी कोविड के बढ़ते नए मामले को लेकर अहम मानी जा रही है। अब तक देशभर में कुल 2,20,01,45,981 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 3408 (0.01प्रतिशत) रिकॉर्ड की गई है। अब तक संक्रमित मरीजों में से 44142242 (98.80त्न) ठीक हो चुके हैं और 530680 (1.19प्रतिशत) मरीजों की जान चुकी है।

चीन में तबाही मचा रहे कोरोना, 3 मामले भारत में मिलने से हडकंप

चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के ओमिक्रोन उपस्वरूप बीएफ.7 के तीन मामले भारत में भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि यह वही वैरिएंट है, जो चीन में तबाही मचा रहा है। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने भारत में बीएफ.7 के पहले मामले का पता लगाया था। उन्होंने कहा कि अब तक गुजरात से दो मामले सामने आए हैं, जबकि ओडिशा से एक मामला सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कोविड समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि अभी तक कोविड मामलों की संख्या में समग्र वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा और उभरते स्वरूपों पर नज़र रखने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। यहां आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चीन के विभिन्न शहर वर्तमान में कोविड के अत्यधिक संक्रामक स्वरूप ओमिक्रोन, ज्यादातर बीएफ.7, की चपेट में हैं, जो बीजिंग में फैलने वाला मुख्य स्वरूप है। इसी के कारण चीन में कोविड संक्रमण के मामलों में व्यापक उछाल आया है। बीएफ.7 ओमीक्रोन के स्वरूप बीए.5 का उपस्वरूप है और इसमें संक्रमण की व्यापक क्षमता होती है तथा इसकी इनक्यूबेशन अवधि कम होती है और इसमें पुन: संक्रमण पैदा करने या उन लोगों को भी संक्रमित करने की उच्च क्षमता होती है, जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। यह अमेरिका, ब्रिटेन और बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों सहित कई देशों में पहले ही पाया जा चुका है।

छात्राओं को ले जा रही बस दुर्घटना का शिकार, 7 की मौत

इंफाल

मणिपुर के नोनी जिले में बुधवार को एक स्कूल बस के पलट जाने से कम से कम सात छात्राओं की मौत हो गई और 18 से अधिक घायल हो गए। कई की हालत गंभीर है। छात्राओं को ले जा रही बस जिले के लोंगसाई इलाके के पास ओल्ड कछार रोड पर मोड़ के पास अचानक पलट गई, जिसमें कम से कम पांच छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां दो छात्राओं ने दम तोड़ दिया।

मरने वालों की संख्या बढने की संभावना है क्योंकि कई छात्राओं की हालत गंभीर है। दुर्घटनास्थल इंफाल से करीब 55 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने कहा कि थम्बलनू हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे दो बसों में नोनी जिले के खौपुम के वार्षिक स्कूल अध्ययन दौरे पर गए थे। जिस बस में छात्राएं सवार थीं, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, आज ओल्ड कछार रोड पर स्कूली बच्चों को ले जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। बचाव अभियान में समन्वय के लिए एसडीआरएफ, मेडिकल टीम और विधायक घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

पैन कार्ड होल्डर्स को लग सकता 10 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभाग फिर एक बार सक्रिय हो गया है। विभाग ने बताया है कि पैन कार्ड होल्डर्स के 1 अप्रैल से फिर लोगों के पैन कार्ड बंद कर देगा। यानि आपको अपना पैन कार्ड 31 मार्च तक आधार कार्ड के साथ लिंक कराना होगा। अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते तो आपको 10 रुपए तक का जुर्माना लग सकता हैं। आप 1000 का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज 30 जून, 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है।

ईडी ने पोंजी स्कीम मामले में कुर्क की 81.7 करोड़ रुपए की संपत्ति

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने हिसार स्थित कंपनी फ्यूचर मेकर्स लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित एजेंट और अन्य के बैंक बैलेंस, जमीन, फ्लैट, दुकानों और आभूषणों के रूप में 81.7 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। आरोपी पोंजी स्कीम चला रहे थे और मासूम लोगों से कई सौ करोड़ रुपये की ठगी कर चुके थे।

ईडी ने हरियाणा और तेलंगाना में दर्ज सात एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

ईडी ने कहा, कंपनी पोंजी स्कीम चलाती थी, जिसमें शीर्ष पर मौजूद लोगों को आधार पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा वहन किए गए नुकसान की कीमत पर लाभ होता था। ईडी की जांच से पता चला है कि बत्रा, जो कंपनी के सॉफ्टवेयर की देखरेख करते थे, ने फर्जी आईडी बनाकर कंपनी के खातों से 59.7 करोड़ रुपये से अधिक के फंड को डायवर्ट किया और अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में डाला। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि डायवर्ट किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा कई शेल कंपनियों के जरिए लॉन्ड्र किया गया, जिन्होंने बदले में कई संपत्तियां खरीदीं और उन्हें कुर्क किया गया है। बत्रा को 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 7 मई को पंचकूला की एक विशेष अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इससे पहले, कंपनी और उसके निदेशकों राधेश्याम, बंसीलाल और अन्य की 261.9 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।

एटा फर्जी एनकाउंटर में 16 साल बाद आया फैसला, पांच को उम्रकैद, चार पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की सजा

गाजियाबाद

गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एटा में साल-2006 में हुए फर्जी एनकाउंटर में 9 पुलिसवालों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसवालों को उम्रकैद और 4 पुलिसवालों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला करीब 16 साल बाद आया है। इसके बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने 5 पुलिसकर्मियों पवन सिंह, श्रीपाल ठेनुआ, सरनाम सिंह, राजेंद्र प्रसाद और मोहकम सिंह को हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी करार दिया है। इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 33-33 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा सिपाही बलदेव प्रसाद, अवधेश रावत, अजय कुमार और सुमेर सिंह को साक्ष्य मिटाने और कॉमन इंटेंशन का दोषी करार दिया है। इनको पांच-पांच साल कैद की सजा और 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस एनकाउंटर में शामिल रहे 10वें पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर अजंट सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है।

गौरतलब है की एटा के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2006 को एक एनकाउंटर पुलिस ने किया था। इसमें राजाराम नामक एक व्यक्ति मारा गया। पुलिस के मुताबिक, ये डकैत था और कई घटनाओं में शामिल रहा था। पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि राजाराम उस रात को भी डकैती की वारदात करने के लिए जा रहा था। राजाराम पेशे से बढ़ई (फर्नीचर कारीगर) था। वो पुलिसवालों के घर भी काम करता था। एनकाउंटर में मारने के बाद पुलिसवालों ने उसकी लाश अज्ञात में दिखाई। राजाराम पर एक भी केस दर्ज नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको डकैत बताकर मार दिया था। जिस सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ था, ये थाना आज कासगंज जिले में आता है।

मृतक राजाराम की पत्नी संतोष कुमारी इस केस को हाईकोर्ट में ले गईं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 18 अगस्त 2006 को बहन राजेश्वरी की तबीयत खराब हो गई थी। अगली सुबह उसे छोड़ दिया जाएगा। अगली सुबह जब राजाराम की पत्नी संतोष कुमारी फिर से थाने पर गई तो पुलिस ने बताया कि उसको पहले ही यहां से घर भेजा जा चुका है। जबकि राजाराम घर नहीं पहुंचा था। 20 अगस्त 2006 को संतोष कुमारी को जानकारी हुई कि गांव सुनहरा के पास पुलिस ने एक एनकाउंटर किया है। अखबारों में मृतक की जो तस्वीर छपी, वो राजाराम की थी। इसके बाद से उसकी पत्नी लगातार केस लड़ती रही।

उत्तर भारत में रेड अलर्ट

कई ट्रेनें निरस्त और उड़ानें भी डायवर्ट- पंजाब-हरियाणा में चलेगी शीतलहर

नई दिल्ली । आरएनएस

उत्तर भारत में भीषण ठंड को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन बुधवार सुबह बी घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

वहीं कोहरे के कारण उडानों पर असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने बुधवार को सूचित किया कि चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ में खराब मौसम के

कारण उड़ानें डायवर्ट की जा रही हैं या वापस दिल्ली लौट रही हैं। डीआईएएल ने यह भी बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता सामान्य है और उड़ान संचालन सुचारू है। देश में 21 दिसंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने को अगले पांच दिनों तक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 को लागू करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं : कैग

नई दिल्ली

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एक ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कार्य योजना की कमी के कारण प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। सरकारी लेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट में कहा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) के पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू नहीं किया जा सका।

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, डेटा गैप थे, जिसके कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ एमओईएफ और सीसी के पास 2015-20 की अवधि के दौरान पूरे देश में प्लास्टिक कचरे की पूरी और व्यापक तस्वीर नहीं थी। ऑडिट ने यह भी देखा कि प्राप्त डेटा एसपीसीबी और पीसीसी को एसपीसीबी द्वारा इसकी प्रामाणिकता और शुद्धता का आकलन करने के लिए मान्य नहीं किया गया था।

कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के सभी तीन सैंपल यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) ने 2015-20 के दौरान हर साल डीपीसीसी को उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे का

डेटा नहीं दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने 2015-20, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने 2015-16 और 2017-18 और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने 2015-16 के लिए डेटा प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, डीपीसीसी को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की लेखापरीक्षा को मुहैया कराए गए आंकड़ों से तुलना करने पर एनडीएमसी के आंकड़ों में 45.97 फीसदी का अंतर देखा गया, जबकि एसडीएमसी के मामले में आंकड़ों में 40 फीसदी का अंतर था।

कैग ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को अपनी एजेंसियों (सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी) के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के उत्पादन, संग्रह और निपटान के संबंध में प्रभावी डेटा संग्रह के लिए एक प्रणाली स्थापित करने और उनके कामकाज की निगरानी करने की जरूरत है।

कैग ने यह भी कहा कि स्थानीय निकायों के समन्वय में सीपीसीबी और राज्य पीसीबी/पीसीसी को समय-समय पर, उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा का व्यापक मूल्यांकन करने और आबादी के आकार, क्षेत्र के भौगोलिक आकार जैसे मापदंडों के अनुसार डेटा एकत्र करने की जरूरत है।

उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को शामिल करके अपने उपनियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं।

रिपोर्ट में एक परियोजना पर निष्फल खर्च को भी दर्शाया गया है और कहा गया है : एमओईएफ और सीसी द्वारा अप्रभावी निगरानी और वित्तीय सहायता जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप डिमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट से पर्यावरणीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ और 73.35 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

चीन पर बहस की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। विपक्षी पार्टियां अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण पर चर्चा की मांग को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र बहस की अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि वह कुछ छिपा रहा है। इस बीच, कांग्रेस के एक नेता के अनुसार, 12 विपक्षी दल बुधवार के विरोध में शामिल होंगे। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उल्लंघनों पर केंद्र का रुख जानना चाहा था और पूछा था कि चीनी राजदूत ने डेमार्च क्यों नहीं जारी किया।

साप्ताहिक
एक जन आंदोलन का आगाज
प्रथम आवाज़
सारंगढ़, गुरुवार, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम : मुख्यमंत्री बघेल पहुँचे ग्राम सोनाखान

- ग्रामीणों से राज्य शासन की योजनाओं पर लिया फीडबैक
- मुख्यमंत्री ने सोनाखान भेंट-मुलाकात में क्षेत्र के विकास के लिए दी अनेक सौगातें
- शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि सोनाखान में खुलेगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल
- सोनाखान में सहकारी बैंक की शाखा प्रारंभ होगी
- गिरौदपुरी में अनुविभागीय कार्यालय (एसडीएम कार्यालय) की घोषणा
- गिरौदपुरी धाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन
- सोनाखान क्षेत्र के 44 गांवों में वीर नारायण सिंह समूह नल जल प्रदाय योजना प्रारंभ करने की घोषणा

प्रथम आवाज | सारंगढ़-बिलाईगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में आज विधानसभा बिलाईगढ़ अंतर्गत विकासखंड कसडोल के ग्राम सोनाखान पहुँचे। मुख्यमंत्री ने यहां क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि सोनाखान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने, सोनाखान में सहकारी बैंक, क्षेत्र के 44 गांवों में वीर नारायण सिंह समूह नल जल प्रदाय योजना प्रारंभ करने, सोनाखान स्थित एकलव्य आवासीय परिसर में विभिन्न संसाधनों हेतु 5.6 करोड़ रूपये स्वीकृति की, ग्राम सोनाखान में ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिये 2.5 करोड़ रूपये की स्वीकृति, सोनाखान के समीपवर्ती ग्राम अर्जुनी, भूसड़ीपाली, महकोनी एवं महकम में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 50 लाख रूपये की स्वीकृति की घोषणा की।

इसी प्रकार उन्होंने गिरौदपुरी में अनुविभागीय कार्यालय (एसडीएम कार्यालय) प्रारंभ करने, गिरौदपुरी धाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र के रूप में करने, जिले के भवनविहीन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन निर्माण, गिरौदपुरी, राजादेवरी से बया पहुँच मार्ग पुल पुलिया सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, चरींदा (बया) से बार होते हुए तुरतुरिया पहुँच मार्ग पुल पुलिया सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, सलिहा से कुशगढ़ विजयमाल होते हुए सांकरा पहुँच मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, टुण्डरा के हाईस्कूल के लिए नये भवन के निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण कर भेंट-मुलाकात का शुभारंभ किया और ग्रामीणों से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर स्कूल शिक्षा, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम संसदीय सचिव एवं विधायक चंद्रदेव राय और सुश्री शकुंतला साहू, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ल, रजक कल्याण बोर्ड लोकेश कन्नौजे, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य गणेश ध्रुव, जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, कलेक्टर रजत बंसल, एएसपी दीपक झा समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भेंट मुलाकात में मानाकोनी की पद्मावती पटेल ने बताया कि उनके समूह ने तीन लाख 71 हजार रुपए का वर्मी कंपोस्ट बेचा है। इस आय से उनके समूह की दस महिलाओं ने आपस में 25-25 हजार रुपए बांटे हैं। शेष रकम उन्होंने बैंक में जमा रखा है। वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से हुई कमाई से उनके समूह की कुछ महिलाओं को अपने बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करने में और कुछ को अपने बच्चों की शादी में बहुत मदद मिली है। समूह की कुछ महिलाओं ने अपने लिए पायल और मंगलसूत्र जैसे गहने भी खरीदे हैं।

सोनाखान में ग्राम भानसी के किसान डिगेश यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे पांच एकड़ के किसान हैं। उनका 75 हजार रुपए का कर्जा माफ हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को खेती से अच्छी आमदनी हो रही है। उन्होंने अपने लिए बुलेट मोटरसाइकिल और पत्नी के लिए हार खरीदा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कर्ज माफी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राशनकार्ड, उचित मूल्य दुकानों के संचालन के संबंध में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने सोनाखान पहुंचने के बाद वहां स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित कर छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतन्त्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही स्मृति स्थल पर स्थापित की गयी शहीद वीर नारायण सिंह के आदम कद मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों का भी श्रीफल एवं शॉल से सम्मान किया गया और उन्हें 10-10 हजार रूपए का चेक भेंट किया।

सोनाखान में क्षेत्र के विकास के लिए 125 करोड़ रूपए के कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन- मुख्यमंत्री ने सोनाखान में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिले के लिए 125 करोड़ 75 लाख रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिसमें 99 करोड़ 36 लाख रूपए के 73 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 26 करोड़ 39 लाख रूपए के 7 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने कार्यक्रम में सोनाखान के दुलेश्वर यादव को ट्रायसायकल प्रदान किया।

बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे किसान से 8.16 लाख की उठाईगिरी

बदपाली चौक पर चाय पीने के लिए रुका था किसान

प्रथम आवाज | कोरबा
(अतुल यादव)

बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा एक किसान उठाईगिरी का शिकार हो गया। मामला उरगा थाना क्षेत्र का है जहां बरपाली चैक पर किसान राकेश गभेल चाय पीने के लिए रुका हुआ था। इसी दौरान मौका पाकर अज्ञात बाइक सवार दुपहिया वाहन की डिग्गी में रखे 8 लाख 16 हजार रुपयों से भरे थैले को पार कर दिया। किसान और आसपास मौजूद लोगों ने लुटेरों को रोकने का काफी प्रयास किया लेकिन रात वे अपनी बाइक में रफ्तार के साथ फरार हो गए।

बैंक से पैसे निकालकर चैक पर चाय पीने के लिए रुकना एक किसान को काफी महंगा पड़ गया। रेकी कर रहे अज्ञात बाइक सवार दो लुटेरों ने किसान की दुपहिया वाहन की डिग्गी में रखे 8 लाख 16 हजार रुपयों से भरे थैले को लेकर फरार हो गए। उरगा थाना क्षेत्र के बरपाली चैक पर यह घटना सामने आई। किसान राकेश गभेल के मुताबिक वो बरपाली स्थित सहकारी बैंक से 8 लाख 16 हजार रुपए निकालकर उसे एक थैले में रखा और अपनी बाइक की डिग्गी में रखकर घर जाने के लिए निकला। इस दौरान बरपाली चैक पर रुककर वह एक होटल में चाय पीने के लिए रुका। मौका पाकर लुटेरों ने रुपयों से भरे उसके थैले को लेकर फरार हो गए। किसान और स्थानीय लोग जब तक हरकत में आते लुटेरे मौके से फरार हो चुके थे।

एक झटके में लाखों का चूना लगने से किसान के तोते उड़ गए। बुरी तरह से घबराया हुआ किसान उरगा थान पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस भी तत्काल हरकत में आई और नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश में जुट गई। हालांकि आरोपियों की अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं मिल सकी है। अपराध कायम कर पुलिस उनकी पतासाजी कर रही है।

सारंगढ़ में भाजपाइयों ने ली प्रेस वार्ता, गौरव दिवस मनाने को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

प्रथम आवाज | सारंगढ़

जिला मुख्यालय सारंगढ़ के मां भवानी रेस्टोरेंट में सारंगढ़ के भाजपा ने प्रेस वार्ता कर कहा की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर इसे गौरव नहीं, बल्कि प्रदेश की स्थिति गर्त में ले जाना बताया है।भाजपाइयों ने सरकार की कमियां गिनाते हुए कहा "भूपेश सरकार का 4 साल लूट, हत्या, चोरी और भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। जितनी बदनामी सरकार की 4 साल में हुई है, उससे छत्तीसगढ़ का सिर झुक गया है. कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल को याद करते हुए हम भाजपा के शासन काल को याद करना चाहते है. भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता था. 15 साल में छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास रहा है.

प्रदेश में कानून व्यवस्था खस्ताहाल- भाजपा नेता ज्योति पटेल ने कहा "प्रदेश अब गांजा तस्करी, ब्राउन शुगर, नशीली गोली, अफीम चरस और शराब की तस्करी समेत ठगी का स्टार्ट अप बन चुका है. अंडरवर्ल्ड गैंग का शूटर रायपुर में मिल रहा है. जुआ सट्टा पुलिस के संरक्षण में हो रहा है. इसके कारण कलेक्टर और SP का IPL की तरह नीलामी होना है. नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार छत्तीसगढ़ की स्थिति कुछ ऐसी है कि दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ देश में सातवें स्थान पर, डकैती के मामले पर पांचवे, फिरौती के मामले पर तीसरे, आत्महत्या के मामले पर छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है.

किसानों के खिलाफ हैं भूपेश बघेल- भाजपा नेता अमित अग्रवाल ने कहा "किसानों के 2 वर्ष के बोनस का भुगतान लंबित है, जिसमें किसानों को कुल 3716.39 करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं, लेकिन यह सरकार किसानों के पैसों को रोककर उनके साथ छल कर रही है. सरकार ने सिर्फ सरकारी बैंकों से लिया गया ऋण ही माफ किया और निजी बैंक से लिए ऋण को माफ नहीं किया. विद्युत पंप कनेक्शन, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण में लगभग 50% की कटौती की गई है. इस वर्ष सरकार 20,550 का लक्ष्य रखा है, जो पूर्व में लंबित प्रकरणों का ही आधा है.

नशे की गिरफ्त में छत्तीसगढ़, देश में दूसरे स्थान पर- भाजपा नेता अरविंद हरिप्रिया ने कहा कि "कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र में 2500 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था. लेकिन 4 सालों में युवाओं को कुछ भी नहीं दिया गया. पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को माफियाओं का गढ़ बना दिया है. छत्तीसगढ़ में 43% युवा नशे की गिरफ्त में है. यह भूपेश बघेल के लिए उपलब्धि हो सकती है कि नशे की गिरफ्त में देश में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है.

गौठान और सेवा सहकारी समिति में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार- भाजपा नेता अजय गोपाल ने कहा की कांग्रेस सरकार जिस गौरव दिवस की ताल ठोक कर अपने सरकार के 4 साल बेमिसाल की बात कर रही है असल में इस दिन को प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए।आज ही के दिन 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का प्रण लिया था जिसका शानदार 4 वर्ष पूरा हो चुका है जबकि एक वर्ष अभी बाकी है।कहा की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार झूठे वादे और छलावा करना ही जानती है इस सरकार ने सेवा सहकारी समितियों में किसानों को ठगने के लिए अपना एक प्रतिनिधि भी समिति अध्यक्ष के रूप में न्युक्त कर रखी जिसमे उन्ही के कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों को ठगने काम कर रही है आलम यह है की किसानो को सेवा सहकारी समितियों में धान बेचने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है कही कही तो उन्हे धान की भराई से लेकर तौल कराने के लिए पैसे देने पड़ रहे है बावजूद मीडिया एवम किसानों से मिलने वाली शिकायतों पर भूपेश बघेल का प्रशासनिक अमला अमल नहीं करती।

सीईओ जी.के. मिश्रा का निलंबन स्थगित-वापस मिला प्रभार

हाईकोर्ट के आदेश उपरांत दी गई पदस्थापना

प्रथम आवाज | कोरबा
(अतुल यादव)

कोरबा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.के. मिश्रा को पिछले दिनों आर्थिक अनियमितता के एक मामले में निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था। 25 नवंबर 2022 को शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा किए गए निलंबन के विरुद्ध मिश्रा ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की। याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए निलंबन पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव झा के द्वारा जी.के. मिश्रा का निलंबन स्थगित कर उन्हें जनपद पंचायत कोरबा का प्रभार पुनः सौंप दिया गया है। आदेश उपरांत सीईओ मिश्रा ने पदभार संभाल लिया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने हितग्राहियों को वितरित की सामग्री

प्रथम आवाज | सारंगढ़-बिलाईगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत सरसींवा विकासखण्ड बिलाईगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया। इनमें बिलाईगढ़ की गणेशी बंजारे, पुनीराम खूंटे, शिव चौहान एवं नागेश्वर निषाद को ट्रायसायकल और भटगांव के समारू छडिया, मेवा श्रीवास, मेघनाथ साहू एवं पुनीराम सिदार को ट्रायसायकल तथा फेकूराम पटेल एवं अमृतलाल पटेल को बैशाखी प्रदाय किया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से 4 बच्चों में मोक्ष रत्नाकर, हंसीका रत्नाकर, बिदिस रत्नाकर, अंकिता खटकर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से 6 बच्चों में दुर्गा जायसवाल, चित्रेश दास, उमंग दास, हिमांशी, लियान एवं कशिश को जाति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

रानीलक्ष्मी बाई आत्मरक्षा योजना

दिव्या रानी भारद्वाज विद्यालयों में बच्चों को दे रहीं कराटे का प्रशिक्षण

प्रथम आवाज | सारंगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा / राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायगढ़ (छ ग) के आदेश क्रमांक / 653 /बालिका शिक्षा /2022-23 रायगढ़ दिनाँक 05/09/2022 के तथा राज्य कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में रानीलक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण अनिवार्यरूप से 30 दिसंबर तक दिया जाना है। उक्त आदेश एवं संकुल शैक्षिक समन्वयक महंगू दास भारद्वाज के मार्गदर्शन में मार्शल आर्ट खिलाड़ी , वेलो एवं ग्रीन बेल्ट प्रमाण पत्रधारी स्थानीय खिलाड़ी कु.दिव्या रानी भारद्वाज द्वारा संकुल केंद्र साल्हे के माध्यमिक शाला बरभांठा , साल्हे , बोरिदा , रींवापार में माह नवम्बर से उक्त शालाओं में प्रशिक्षण दे रही है। कु. दिव्या रानी भारद्वाज मेधावी कराटे खिलाड़ी है । एवं फिरत राम भारद्वाज जी व्याख्याता शा उ मा विद्यालय सरसींवा ग्राम छिंद सारंगढ़ निवासी के सुपुत्री हैं। जो लगातार कराटे के क्षेत्र में विभिन्न जिला स्तरीय /राज्य स्तरीय खेलों में अपनी प्रतिभा से ख्याति प्राप्त की है। शासन के आदेशानुसार माध्यमिक शालाओं में रानीलक्ष्मी बाई आत्मरक्षा कराटे प्रशिक्षण सभी अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। परंतु शासन की उक्त प्रशिक्षण की लाभ बहुत से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को नहीं मिल पा रही है। जो कि चिंतनीय विषय है। उक्त 30 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा 5000 रु.राशि संबंधित प्रशिक्षक हेतु प्रधान पाठकों को जारी किया गया है। पिछले वर्ष लगभग अधिकांश स्कूलों में यह प्रशिक्षण नहीं कराया गया।जिस कारण राशि लेप्स हो गया और उक्त प्रशिक्षण का लाभ छात्राओं को नहीं मिल पाया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन एवं प्रशासन को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तथा उक्त प्रशिक्षण का लाभ सभी विद्यार्थियों को प्रदाय किया जाने की आवश्यकता है। ताकि बालिकाओं को आत्मरक्षा की प्रशिक्षण जरूर मिलना चाहिए।

रेत तस्करों पर कोतवाली पुलिस ने कसा शिकंजा

एफआईआर के बाद होगी गिरफ्तारी

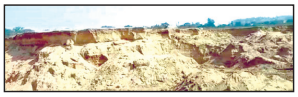

प्रथम आवाज | कोरबा
(अतुल यादव)

कोरबा (ईएमएस) कोरबा जिले के प्रमुख रेत घाट को खनिज विभाग ने स्वीकृति ना मिलने के अभाव में बंद कर रखा है। ऐसे में रेत तस्करों की जमकर मजे हो रहे है। रेत तस्कर खनिज विभाग की आंखों में धूल झोंककर लगातार रात के अंधेरे में मोतीसागर पारा, गेरवाघाट, डेंगूरनाला सहित अन्य घाटों में घुसकर बड़े पैमाने पर रेत की चोरी कर रहे हैं और पूरे शहर में बेच रहे हैं। अवैध कारोबार से रेत तस्कर मालामाल हो रहे हैं। लोगो ने आरोप लगाया हैं कि खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। रेत तस्कर शहर के मोतीसागरपारा स्थित घाट में घुसकर जमकर रेत की निकासी कर रहे हैं, तस्करों ने कब्र तक को तोड़ डाला था। लोगों ने विरोध किया तो रेत तस्करों की करतूत का पता नगर कोतवाल रूपक शर्मा को चला तो वे तत्काल दलबल सहित मौके पर पहुंचे। जहां का हाल देखकर वे भी दंग रह गए। कब्र तोड़कर आमजन की भावना से खिलवाड़ मानकर रेत तस्करों पर नाराज होते हुए तत्काल एफआईआर लिखा। जिसमें आमजन द्वारा बताए संदिग्धों के खिलाफ धारा 297, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। अब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। कोतवाली पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों में छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। उम्मीद हैं पुलिस जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करेगी।

जंगल में लगी कक्षा

वन मितान जागृति कार्यक्रम के तहत 58 छात्रों के साथ शिक्षक भी हुए शामिल

प्रथम आवाज | कोरबा
(अतुल यादव)

कोरबा (ईएमएस) वन मितान जागृति कार्यक्रम के तहत कोरबा वनमंडल डीएफओ अरविंद पी.एस. के निर्देशानुसार एवं उप वनमण्डलाधिकारी दक्षिण कोरबा आशीष खेलवार के मार्गदर्शन में कुदमुरा परिक्षेत्र के कुदमुरा हाई स्कूल के छात्रों को लेबंद वन भ्रमण एवं कलमी टिकरा जलाशय में जंगल की खूबसूरती से रूबरू कराया गया, कार्यक्रम में शाला से अपने शिक्षकों के साथ 58 बच्चो ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, यह इन छात्रों के लिए पहला मौका था कि उनकी कक्षाएं पहली बार खुले जंगलों में लगी।

छात्रों को तीन दलों में बांटा गया और उन्हें अपने से ग्रुप का नाम रखने को कहा गया जिसमें से छात्रों में अपने दल का नाम लायन, टाइगर और साल वृक्ष के नाम पर रखा, उन्होंने पेड़ो को पहचानना सीखा उनके बोटनिकल नाम को जाना, पेड़ो के विभिन्न रहस्यों को जाना, जंगल भ्रमण के दौरान बच्चों को वनों में 2 किलोमीटर तक भ्रमण किया उसके साथ ही वन जड़ी-बूटी का महत्त्व एवं उपयोगिता के बारे में जाना, विभिन्न पक्षियों, कीड़ो, तितली के बारे में अध्ययन किया, पूरे भ्रमण के दौरान छात्रों में बहुत ऊर्जा का संचार दिखा, भ्रमण के पश्चात जितेंद्र सारथी के द्वारा सांपो के बारे में बताया गया साथ ही हाथी के महत्व को भी समझाया, दिनेश कुमार ने पेड़ों की पहचान कराई साथ ही सरोजनी गोयल ने वन में मिलने वाले जड़ी-बूटी के महत्त्व को बताया।

पूरे कार्यक्रम से बच्चों में निडरता, नेतृत्व, सहयोग जैसे गुणों के विकास में सार्थक साबित हुआ, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मेलाल कंवर, सरपंच बरपाली एवं महाप्रसाद राठिया, उपसरपंच आहिबरन प्रजापति, प्रबंधक बृजलाल राठिया, वन प्रबंधन समिति बरपाली परशुराम कंवर, प्राचार्य नीता चक्रवर्ती, समस्त शिक्षक, वन परिक्षेत्र अधिकारी घुटुर साय पैकरा, ड्यूटी रेंजर संजय केशकर, सनथ कुमार बरीहा, भरत लाल साहू, शिशुपाल सिंह कंवर, दीपक कंवर, मिथलेश सिदार, उपेंद्र चौहान, किरण कुमार राठिया एवं हाथी मित्र दल के सदस्य उपस्थित रहे।

साप्ताहिक
एक जन आंदोलन का आगाज
प्रथम आवाज़
सारंगढ़, गुरुवार, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022

सुखती धान के नाम पर किसानों के मेहनत पर बट्टा मार रहे समिति प्रबंधक

सारंगढ़ के कई उपार्जन केंद्रो में शासन के निर्देशो का खुला उल्लंघन, किसान परेशान

प्रथम आवाज | सारंगढ़

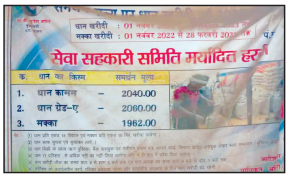

सारंगढ़ क्षेत्र की धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों के आंखों के सामने धांधली हो रहा है लेकिन नियम का हवाला देकर किसानों की मुंख बंधिर कर दिए जा रहे है प्रबंधक जहाँ किसानों से तौल मे 200 से 300 ग्राम धान बढ़ा कर लिया जा रहा है और सोचने वाली बात यह है कि धान की नमी 15 प्रतिशत होने के बाद भी अत्यधिक धान किसानों से हर तौल पर लिया जा रहा है आपको बता दे ताजातरीन मामला हरदी उपार्जन केन्द्र का है जहाँ किसानों के धान की नमी, नियमानुसार 17 से कम तक का लिया जा रहा है लेकिन फिर भी सूखती के नाम पर 200 से 300 ग्राम धान अधिक हर तौल पर लिया जा रहा है ,ऐसे ही एक किसान का तौल हुआ धान, फिर से तौल कराया गया, जहाँ पर लगभग 500 से 600 ग्राम धान इजाफा हुआ जिसमे सूखती के रूप में 200 से 250 ग्राम और दे भी दिया जाए तब भी अत्यधिक धान किसानों से लिया जा रहा है,

तौल करने वाले हेमाल द्वारा बताया गया कि जिस धान को तौल किया गया था उस धान का नमी 15 प्रतिशत था। इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों के साथ कैसे नमी के नाम पर लूट किया जा रहा है अगर इस आंकड़े को धान की पूरी खरीदी के अनुसार देखा जाए तो सैकड़ों क्विंटल धान उपार्जन केन्द्र में शुद्ध बचेगा जिसका सारा लाभ हरदी वाले प्रबंधक उठाएंगे और लाखो का मुनाफा उठाएंगे ।अगर इसकी पूर्ण जांच करे तो सारा खेला सामने आ जाएगा इतना ही नहीं कलेक्टोरेट कार्यालय की खाद्य शाखा मे लिखा हुआ है कि धान सुबह 9 बजे से तौल शुरू होना है लेकिन तौल के नियम को ताख में सारा खेल खेला जा रहा है,अधिकतर उपार्जन केन्द्रों में 2 बजे के बाद ही तौल किया जा रहा है जिसके चलते किसानो को देर रात तक उनके बारी का इंतजार करना पड़ रहा है सुबह से किसान बैठे बैठे शाम रात हो जाता है। वही तौल जल्दी नहीं होने की वजह से किसान काफी परेशान नजर आते है। आपको बता दे हरदी धान उपार्जन केंद्र में नोडल अधिकारी नही रहने के कारण प्रबंधक का मनमानी चरम सीमा पर है।

चिरायु से लाभान्वित बच्चे हुए मुख्यमंत्री से रूबरू

प्रथम आवाज | सारंगढ़

मुख्यमंत्री भेंट वार्ता कार्यक्रम हमारे नए जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सरसींवा में आयोजित हुए जिसमे चिरायु योजना से लाभान्वित बच्चों से सीधे मुलाकात हुई इस अवसर पर चिरायु योजना से-

1. निधी साहू , मल्दी, (दिल मे छेद) 2. आरुषि सारथी , अमलडीहा, (दिल में छेद) 3. योगेश्वरी केवट, मिर्चिद, (दिल मे छेद) 4. प्रीति बंजारे , जुनवानी , (दिल मे छेद) 5. प्रकुल, (होंठ व तालु में छेद,) सरधाभाठा के लोग शामिल हुए थे। तथा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से हाट बाजार 1. परदेशी राम कुर्रे ,जोगेशरा (मधुमेह) 2. भगराम साहू , चोरभट्ठी (ब्लड प्रेशर) 3. सब्बू लाल , बम्हनपुरी (ब्लड प्रेशर) 4. नवधा राम , बम्हनपुरी (मधुमेह) से ग्रसित हितग्राहि इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। सभी अपनी अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मुंखिया ने भी इनकी बात ध्यान से सुना और खुशी जाहिर की।

चिरायु योजना और हाट बाजार क्लिनिक योजना से लाभान्वित इन लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी।

इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ0 फरिहा आलम व मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 एफ0आर0 निराला के निर्देशन में तथा बी0एम0ओ0 सारंगढ़ डॉ0.आर0 एल0 सिदार, डी0पी0एम0 एन0 एल0 इज़ारदार, जिला नोडल अधिकारी डॉ0 पी0 डी0 खरे, बी0एम0ओ0 बिलाईगढ़ डॉ0 पी0 वैष्णव के कुशल मार्गदर्शन में चिरायु व हाट बाजार क्लिनिक से लाभान्वित मरीजों को योजनानुसार चिरायु टीम के सहयोग सम्मिलित किया गया था।

साथ ही बिलाईगढ़ चिरायु टीम के डॉ0 नेहा पाटले, डॉ0 लकेश्वर पटेल, डॉ0 श्रीकांत शर्मा, फार्मासिस्ट मिथलेश रत्नाकर व फार्मासिस्ट अनिल निराला का विशेष सहयोग रहा।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के प्रभारी सहायक आयुक्त ट्रायबल का स्थानांतरण

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ त्वरित अमल

- बिलाईगढ़ क्षेत्र में भेंट-मुलाकात के दौरान आदिम जाति विकास विभाग के बारे में मिली थी शिकायतें
- मुख्यमंत्री ने अधिकारी के स्थानांतरण और जांच के दिए थे निर्देश

प्रथम आवाज | सारंगढ़-बिलाईगढ़

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के आदिवासी विकास विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त पी.सी.लहरे की सेवाएं मूल विभाग में वापस लेते हुए आगामी आदेश तक उन्हें संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। पी.सी.लहरे का मूल पद अनुसंधान अधिकारी है। आज दोपहर मंत्रालय से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बिलाईगढ़ में कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान जहां शिकायतें आ रही हैं, वहां कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए और यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हो।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात के दौरान आम जनता से आदिम जाति विकास विभाग के बारे में मिली लेन-देन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आज बिलाईगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारी का स्थानांतरण करने और शिकायतों की जांच के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर त्वरित अमल करते हुए

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत रामटेक में बन रहा सड़क चढ़ा भ्रष्टाचार का भेंट

थूक पालिश कर अधिकारी और ठेकेदार बना रहे मोटा माल, जाँच ज़रुरी

प्रथम आवाज | सारंगढ़

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के कई क्षेत्रों में सड़क मरम्मत का काम चल रहा है जहा भ्रष्टचार की सीमा इतना पार हो चुका है उसके बाद भी किसी भी अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है घटिया सड़क आज शोशल मीडिया की सुर्खियो में है और सारंगढ़ जिला खूब भ्रष्टाचारी का नाम कमा रहा है रामटेक मे बन रही सड़क मरम्मत का कार्य घटिया है गुणवत्ता विहीन सड़क साफ दिखाई दे रहा है सड़क अभी पूरी तरह से बना नहीं उखड़ना शुरू हो चुका है ये तस्वीर सड़क मरम्मत दिखावे का पर्दा हटा दिया है ऐसे महान ठेकेदार को सरकार करोड़ों रुपए दे कर सड़क बनाने जिम्मा दे देता है और शर्म तक नहीं आती उनके जांच अधिकारी को घटिया स्तर हीन सड़क को अच्छी और पक्की बताने मे हिचकिचाहट तक नहीं होता प्रधानमंत्री सड़क के जिम्मेदार अधिकारी की आखो मे पट्टी बांध ठेकेदार के हवाले छोड़ सरकारी तनख्वाह खा रहे है करोड़ों की सड़क जिला से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर बन रहा है जिला के बड़े बड़े अधिकारी यहां बैठे हुए है अब उनसे ही जानता आश उम्मीद लगाया बैठा है कि नया जिला है विकास होगा अच्छा होगा लेकिन यहां तो भ्रष्टचारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें अधिकारियो का तनिक भी चिंता नहीं और ना ही डर दिखाई दे रहा है

सुनील राम दास ठेकेदार की मेहरबानी से बन रहा घटिया सड़क- वहीं सूत्र बताते है कि रामटेक मे बन रही सड़क का ठेकेदार रायगढ़ का सुनील राम दास बताया जा रहा है करोड़ों रुपए सरकार ने उसे एक अच्छी सड़क बनाने के लिए दिया जिसका खूब फायदा उठा रहे है स्तरहीन सड़क बनाकर लाखो मुनाफा कमाना मकसद बन गया है साहब का ,अधिकारी इतना भ्रष्ट हो गया कि आंख मुदे बैठा है ठेकेदार साहब आमजन का भी थोड़ा ख्याल रख लीजिए आपके भरोसे सरकार करोड़ों रुपए दे रहा है सरकार और जनता आप से एक अच्छी और पक्की सड़क की उम्मीद कर रहा है लेकिन भ्रष्टचार का चादर बिछा कर साहब खुद डोल रहे है अब देखना यह है कि अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद किया कदम होगा किया जनता को मिलेगा उम्मीद की सड़क या भ्रष्टाचारियों का काला चादर सब ढक देगा।

जिले में आधार सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित

सीईओ निश्रा ने ली गठित समिति की पहली बैठक

प्रथम आवाज | रायगढ़

शासन के निर्देशानुसार जिले में आधार सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। जिसकी आज पहली बैठक सीईओ जिला पंचायत अभिनाश मिश्रा की अध्यक्षता कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। समिति गठन का मुख्य उद्देश्य जिले में पर्याप्त मात्रा में आधार सेवा केंद्र स्थापित किया जाना है, जिससे लोगों को आधार सेवा के लिए अधिक दूरी तय न करना पड़े एवं सुलभता से आधार सेवाएं प्राप्त हो सके। इसके अलावा आधार पंजीयन संख्या में वृद्धि करना है। साथ ही जिनका आधार कार्ड वर्ष 2015 से पूर्व बना हो, उनका वर्तमान दस्तावेज के साथ अपडेट किया जाना है। जिसके लिए पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर आधार शिविर के माध्यम से किया जाना है। जिसके लिए न्यूनतम 50 रूपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी में बच्चों का आधार एनरोलमेंट किया जाएगा, जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार पंजीयन की सुविधा प्रदान की जायेगी। सभी लोगों के साथ बच्चों के आधार व अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन, आधार लिंक जन्म प्रमाण पत्र का क्रियान्वयन, आधार में मोबाइल लिंक का क्रियान्वयन तथा सेवा केंद्रों की निगरानी का कार्य किया जाएगा। बैठक में डिप्टी कलेक्टर बेरनादत्त एक्का, जिला शिक्षा अधिकारी बाखला, लीड बैंक अधिकारी अमीनाथ महाली, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अतुल दाण्डेकर, सहित अन्य उपस्थित रहे।

भारत माता चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किया गया पुतला दहन

प्रथम आवाज | सारंगढ़

भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों के जेल जाने से त्रस्त भूपेश बघेल द्वारा बजरंगी गुंडे जैसे शब्दों का प्रयोग कर हिन्दू समाज को अपमानित करने के कृत्य से नाराज समस्त हिन्दू संगठन एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं और सनातनियों ने भारत माता चौक में भूपेश बघेल का पुतला जला कर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में प्रमुख रूप से युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष अक्षत स्वर्णकार के योजना में त्वरित इस विषय पर एकत्रीकरण करने को कहा कि बजरंग बली जी एवं भगवा रंग को अपमानित करने वालो को कभी हिन्दू माफ नही करेगा बजरंगी गुंडा बोलना और भगवा धारियों को अपमानित किये जाने पर आक्रोश व्यक्त कर घोर निंदा प्रकट किया।

उक्त विरोध प्रदर्शन और भी उग्र रूप में हो सकता था किंतु हिंदुओं के संस्कार देख सभी संतुलित रूप में हुआ, नगर के हिन्दू धर्म प्रमुख व्यक्ति एवं युवा मोर्चा सारंगढ़ के कार्यकर्ता सामिल हुए। मंडल अध्यक्ष अमित तिवारी, के.के तिवारी, पुलकित चंद्रा , सतीस यादव, अवधेस ठेठवार, पवन देवांगन, देवकुमारी लहरे, राजेश जायसवाल, महंत बंशी दास, तुलाराम सोनवानी, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष नयन बेहार, सूरज गुप्ता, प्रियव्रत स्वर्णकार, राजेश स्वर्णकार, उमेश विश्वकर्मा, डोरीलाल चंद्रा, कुंदन कुर्रे, दिलीप साहू, आर्यन मिश्रा, राहुल केशरवानी, हरीश स्वर्णकार, नीलेश यादव, प्रिंश केवट, आर्यन केवट, सिदार्थ देवांगन, हर्ष पटेल, वैभव गुप्ता साथ ही सभी सारंगढ़ के हिंदू समाज का सहयोग रहा है।

कृषि विभाग में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु 26 तक आवेदन आमंत्रित

प्रथम आवाज | रायगढ़

कार्यालय उप संचालक कृषि रायगढ़ अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वॉटरशेड) अंतर्गत स्वीकृत परियोजना में परियोजना स्तर पर सचिव 12 पद, डब्ल्यूडीटी (समूह विकास) एक पद, डब्ल्यूडीटी (यात्रिकी) एक पद, डब्ल्यूडीटी (आजीविका) एक पद एवं एक पद लेखापाल सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा जिला स्तर में तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी)एक पद, प्रबंधन विशेषज्ञ एक पद एवं लेखापाल एक पद की संविदा भर्ती (एक वर्ष के लिए)किया जाना है। इच्छुक आवेदक 26 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं।

गरीबों के आवास रोककर उनका अधिकार छीन रहा है भूपेश सरकार - हरिनाथ खुंटे

प्रथम आवाज | सारंगढ़

प्रदेश भाजपा द्वारा पूरे में वृहद् रूप से सभी ग्राम पंचायतों में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम चला कर प्रतीक्षा सूची में रहे हितग्राहियों के अधिकार के लिए प्रदेश भर में पंचायत स्तर तक कार्यक्रम तय किया गया है। इसी दौरान भेड़वन मंडल में ग्राम रेडा में भाजपा युवा नेता हरिनाथ खुंटे ने सैंकड़ों हितग्राहियों के मध्य पहुँच कर प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में ग्रामीणों को सम्बोधित किया।

कार्यक्रम के दौरान खुंटे ने कहा की राज्य में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी है तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के गरीब जनता के 16 लाख परिवारो का आवास रोक दिया है। खुंटे ने आगे कहा की जब प्रदेश में भाजपा सरकार था तब प्रत्येक ग्राम में युद्ध स्तर पर आवास बनाने का कार्य चल रहा था, किंतु वर्तमान सरकार ने गरीबों के हक़ का पैसा रोक प्रदेश के हितग्राहियों के साथ अन्याय किया है। हरिनाथ खुंटे ग्रामीणों को बताया कि जब तक ग़रीबों के हक़ का आवास उनको नही मिल जाता तब तक भाजपा कार्यकर्ता भूपेश बघेल के ख़िलाफ़ सड़क पर आंदोलन करता रहेगा।

बता दे की राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना अंशतः राशी देने से इनकार कर दिया जिस कारण प्रदेश के लाखों गरीब परिवारो का आवास नही बन पाया।इस कार्यक्रम में हरिनाथ खुंटे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुख्य वक्ता के रूप उपस्थित रहे साथ में बुधनाथ गिरी गोस्वामी जिला कार्यकारिणी सदस्य संस्कृति प्रकोष्ठ,महामंत्री बृहस्पति यादव, मंडल पदाधिकारी रामेश्वर गिरी, विरेंद्र कुर्रे सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया शहीद वीरनारायण सिंह इको टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण

विशेष धातु से निर्मित प्रदेश का पहला ऑडियो विजुअल सेटअप वाले म्यूजियम का हुआ अनावरण

प्रथम आवाज | सारंगढ़-बिलाईगढ़

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम सोनाखान पहुंचे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में बनाए गए इको टूरिज्म सर्किट एवं म्यूजियम का शुभारम्भ किया। सोनाखान के कूरूपाठ के घने जंगलों में प्रकृति के बीच इस कलाकृति को आकार दिया गया है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला ऐसा म्यूजियम है, जहां ऑडियो-विजुअल सेटअप और एक विशेष धातु कॉर्टेन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शित किया गया है।

सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शहीद वीरनारायण सिंह की गौरव गाथा को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष तरह के कॉर्टेन स्टील का प्रयोग किया गया है। बताया गया कि कॉर्टेन स्टील एक तरह का ऐसा मेटल है, जिसमें पहले से जंग की एक परत लगी हुई होती है। खास बात यह है कि यह धातु प्रकृति को हानि नहीं पहुँचाती। कूरूपाठ पहाड़ की हरियाली के बीच इसकी नयनाभिराम सुंदरता देखते ही बनती है।

कॉर्टेन स्टील के बने लम्बे और सुंदर पैनल्स पर शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी उकेरी गई है, जिसका अवलोकन दिन के उजाले के साथ ही रात में भी देखा जा सकता है। लाइट के अद्भुत सेटअप इसे खास और अलग बनाते हैं। सभी पैनल एक ऑडियो सेटअप के साथ है जहां सोनाखान के पराक्रमी शहीद वीर नारायण सिंह के जन्म से लेकर क्रांति और बलिदान को सुना जा सकता है। यह ऑडियो हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा में उपलब्ध है। पर्यटक अपनी पसंद मुताबिक ऑडियो की भाषा का चयन कर सकता है। देश में कॉर्टेन स्टील का उपयोग विभिन्न महान परियोजनाओं में कलाकृतियां बनाने के लिए किया जा चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बिहार म्यूजियम और कई देशों के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट में इसका उपयोग किया गया है। इस नवाचार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान का समापन, चिन्हांकित मरीजों का उपचार प्रारंभ

प्रथम आवाज | सारंगढ़-बिलाईगढ़

कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी के निर्देशानुसार 01 दिसंबर से जिले में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एफ.आर.निराला के मार्गदर्शन में जिले में टीबी एवं कुष्ठ सघन जांच खोज अभियान के अंतर्गत अब तक टीबी के 256 मरीजों के सत्यापन में 34 नए रोगी चिन्हांकित हुए हैं, वही कुष्ठ के 260 शंकाग्रद मरीजों के सत्यापन में 76 नए रोगी चिन्हांकित हुए हैं। इन मरीजों का उपचार आज जिला चिकित्सालय में प्रारंभ हो गया है। घर-घर जाकर मरीज खोजने का आज अंतिम दिन था। 16 दिसंबर से क्षेत्रीय आरएचओ के द्वारा भी वैलीडेशन किया जाएगा। जिले के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय में बुलाकर मरीजों का सत्यापन किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक हरिनाथ खुंटे द्वारा पूर्णिमा ट्रेडर्स संस्कार स्कूल कैंपस, बोंदाटिकरा रोड, गढ़उमरिया, रायगढ़ छग से मुद्रित तथा 42- खुड़ूभाठा, सारंगढ़ ज़िला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छग 496450 से प्रकाशित।
संपादक- हरिनाथ खुंटे 7803022000, 9300678767, Email- prathamaawaz@gmail.com, web- www.prathamaawaz.com